

भारतीय अर्थव्यवस्था और इम्पॉसबिल ट्रिनिटी

प्रलम्ब के लिये:

इम्पॉसबिल ट्रिनिटी, [भारतीय रज़िर्व बैंक](#), [मौद्रिक नीति](#), [वदेशी मुद्रा भंडार](#)

मेन्स के लिये:

इम्पॉसबिल ट्रिनिटी को संभव बनाने में चुनौतियाँ, भारत की मुद्रा गतिशीलता

[स्रोत: बज़िनेस लाइन](#)

चर्चा में क्यों?

वर्तमान में [भारतीय रज़िर्व बैंक \(RBI\)](#) और भारतीय नविकों को "इम्पॉसबिल ट्रिनिटी" पर काबू पाने में एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

इम्पॉसबिल ट्रिनिटी:

परिचय:

- इम्पॉसबिल ट्रिनिटी, या त्रिलम्बा, इस विचार को संदर्भित करता है कि एक अर्थव्यवस्था स्वतंत्र [मौद्रिक नीति](#), नश्वर वनिमिय दर नहीं बनाए रख सकती है और एक ही समय में अपनी सीमाओं के विपरीत पूंजी के मुक्त प्रवाह की अनुमति नहीं दे सकती है।
 - एक नश्वर वनिमिय दर व्यवस्था में घरेलू मुद्रा अन्य वदेशी मुद्राओं जैसे अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग आदि की एक बास्केट से जुड़ी होती है।
- एक सक्षम नीति निर्माता, किसी भी समय, इन तीन उद्देश्यों में से दो को प्राप्त कर सकता है।
- यह विचार 1960 के दशक की शुरुआत में कनाडा के अर्थशास्त्री रॉबर्ट मंडेल और ब्रिटिश अर्थशास्त्री मार्कस फ्लेमिंग द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रस्तावित किया गया था।
- इम्पॉसबिल ट्रिनिटी अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र और मौद्रिक नीति में एक मौलिक अवधारणा है।
- यह उन अंतरनिति चुनौतियों का वर्णन करती है जिनका सामना देश अपनी वनिमिय दर और पूंजी प्रवाह से संबंधित तीन विशिष्ट नीतित उद्देश्यों को एक साथ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।

चुनौतियाँ:

- जब कोई देश मुक्त पूंजी प्रवाह और नश्वर वनिमिय दर को प्राथमिकता देता है, तो वह अपनी मौद्रिक नीति पर नियंत्रण खो देता है, जिससे वह बाह्य आर्थिक दबावों के प्रति संवेदनशील हो जाता है।
- यदि कोई देश एक नश्वर वनिमिय दर और स्वतंत्र मौद्रिक नीति बनाए रखना चाहता है, तो उसे अपनी सीमाओं के विपरीत धन के प्रवाह को सीमित करने के लिये पूंजी नियंत्रण लागू करना होगा।
- स्वतंत्र मौद्रिक नीति और मुक्त पूंजी प्रवाह का विकल्प चुनने के लिये वनिमिय दर में उतार-चढ़ाव को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, जिससे संभावित रूप से अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।

इम्पॉसबिल ट्रिनिटी के उदाहरण:

- वभिन्न देशों ने इम्पॉसबिल ट्रिनिटी की चुनौतियों का सामना किया है, जिनमें से कुछ उल्लेखनीय उदाहरण वर्ष 1997 में एशियाई वित्तीय संकट और वर्ष 1992 में यूरोपीय वनिमिय दर तंत्र संकट हैं।
 - इन संकटों को आंशिक रूप से प्रभावित देशों की नश्वर वनिमिय दरों, स्वतंत्र मौद्रिक नीतियों और मुक्त पूंजी प्रवाह को एक साथ बनाए रखने में असमर्थता हेतु ज़िम्मेदार ठहराया गया था।

भारत का इम्पॉसबिल ट्रिनिटी से जूझना:

- इम्पॉसबिल ट्रिनिटी को संबोधित करने के लिये रणनीतियाँ और कार्य:
 - ब्याज दरों का प्रबंधन:

- अमेरिकी फेडरल रज़िर्व की तुलना में RBI ब्याज़ दरें बढ़ाने में सतर्क रहा है।
 - दरें बढ़ाने की अनछिछा मंदी उत्पन्न होने के भय से प्रेरित है, खासकर वर्ष 2024 में आगामी चुनावों के साथ।
- कम ब्याज़ दर मध्यस्थता अमेरिका (वशिव की आकर्षण मुद्रा) में पूंजी की उड़ान और भारतीय रुपए के आसन्न मूल्यह्रास का संकेत देती है।
- वदेशी मुद्रा भंडार की संरचना:
 - भारत के **वदेशी मुद्रा भंडार** में मुख्य रूप से 'हॉट मनी' (वदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) से जो मध्यस्थता के अवसरों का लाभ उठाने के लिये घरेलू ऋण या इक्विटी बाज़ारों में निवेश करते हैं) और कॉर्पोरेट उधार (उदाहरण के लिये, अडानी ग्रीन एनर्जी, वेदांता, आदि) शामिल हैं, ना कवियापार से कमाया गया धन।
 - व्यापार के माध्यम से अर्जति नहीं किये गए भंडार पर विश्वास करना मुद्रा स्थिरता बनाए रखने के लिये चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
 - पूंजी नियंत्रण लागू करना:
 - भारत ने पूंजी प्रवाह को नियंत्रित करने के लिये विभिन्न उपाय लागू किये हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता अभी अनश्चित बनी हुई है।
 - पूंजी बहर्प्रवाह को नियंत्रित करने के नीतित उपाय:
 - आयात प्रतिबंध और लाइसेंसिंग नीतियाँ:
 - भारत ने पूंजी के बहर्प्रवाह को सीमित करने की त्वरित प्रतिक्रिया के रूप में, विशेष रूप से **इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध** लगाया।
 - इन प्रतिबंधों को बाद में घरेलू वनिरमाण सीमाओं के कारण लाइसेंस-आधारित आयात नीतियों में बदल दिया गया।
 - हालाँकि, ये उपाय अनजाने में पूंजी के बहर्प्रवाह को रोकने के बजाय आपूर्ति-तन्त्र मुद्रास्फीति में योगदान कर सकते हैं।
 - कर दरों में परिवर्तन:
 - भारत ने पूंजी के बहर्प्रवाह को प्रतिबंधित करने के साधन के रूप में आउटबाउंड प्रेषण पर कर दरों को 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया है।
 - 'इम्पॉसबिल टरनिटी' के प्रबंधन में इस कर वृद्धि की प्रभावशीलता जाँच के दायरे में है।
 - भारत की आर्थिक स्थिति पर चीन का प्रभाव:
 - **चीन की अपस्फीति** और विभिन्न दरों में कटौती का उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। चीनी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जुलाई में पिछले वर्ष की तुलना में 0.3% गिर गया। इसके अतिरिक्त, चीनी युआन के मुकाबले INR में 4% की वृद्धि हुई है।
 - भारतीय रुपए के मज़बूत होने के परिणामस्वरूप चीन से आयात में वृद्धि हो सकती है जो अंततः भारत के व्यापार संतुलन तथा मुद्रा गतिशीलता प्रभावित कर सकती है।
 - चीनी मुद्रा युआन के मूल्यह्रास से वैश्विक बाज़ारों में भारत का निर्यात कम प्रतिस्पर्द्धी हो सकता है।
 - वदेशी संस्थागत निवेशक (Foreign Institutional Investors- FIIs) और भारतीय ऋण:
 - वदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय ऋण प्रतिभूतियों की हसिसेदारी बेचे जाने तथा वदेशों में अधिक लाभदायक निवेश की तलाश करने से वदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि देखी जा रही है और वदेशी मुद्रा बाज़ार में भारतीय रुपया कमज़ोर हो रहा है।

भारतीय निवेशकों के लिये इम्पॉसबिल टरनिटी के नहितार्थ:

- रुपए के मूल्यह्रास से सुरक्षा:
 - सूचना प्रौद्योगिकी और फार्मा जैसे क्षेत्रों में निवेश, जिनमें कमाई मुख्य रूप से डॉलर में होती है, रुपए के मूल्य में गिरावट कम कर सकते हैं।
 - रुपया कमज़ोर होने के समय इन कंपनियों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में संभावित वृद्धि लाभकारी रटिर्न दे सकती है।
- वदेशी में निवेश में विविधता लाना:
 - निवेशकों को 'इम्पॉसबिल टरनिटी' द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को स्वीकार करने के लिये स्वयं को अनुकूलित करना चाहिये।
 - चुनौतीपूर्ण आर्थिक स्थिति में, पूंजी की सुरक्षा के लिये अंतर्राष्ट्रीय परसिप्ततियों में निवेश करना आवश्यक हो जाता है।

आगे की राह

- भारत को पूंजी नियंत्रण उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर ध्यान देना चाहिये। इन उपायों से मुद्रा स्थिरता बनाए रखने और वदेशी निवेश को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।
- देश को सक्रिय रूप से अपने वदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लानी चाहिये और वदेशी निवेशकों के 'हॉट मनी' पर बहुत अधिक निर्भर रहने के बजाय व्यापार के माध्यम से लाभ अर्जति करने का लक्ष्य रखना चाहिये।
- इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष वदेशी निवेश को आकर्षित करने से मुद्रा स्थिरता में मदद मिल सकती है और रुपया मज़बूत हो सकता है।
- भारतीय रज़िर्व बैंक को मुद्रास्फीति नियंत्रण और वदेशी निवेश को आकर्षित करने संबंधी कार्यों पर विचार करते हुए ब्याज़ दरों के संदर्भ में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। ब्याज़ दर का क्रमिक समायोजन इस संतुलन को हासिल करने में मदद कर सकता है।

